भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3929
उत्तर देने की तारीख 18 मार्च, 2020

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

3929. श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :
श्री बिद्युत बरन महतो :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संचार मंत्रालय के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को इस संबंध में जनता से क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) क्या आईपीपीबी की स्थापना से देश में रोजगार उत्पन्न हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आईपीपीबी द्वारा खोली गई शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्व बैंक जैसे वैश्विक बैंकिंग संस्थान सहित विभिन्न संस्थान आईपीपीबी से जुड़ने के लिए रुचि दिखाते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख) जी, हां। सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना 100% सरकारी इक्विटी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कंपनी के रूप में की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईपीपीबी को अनुसूचित भुगतान बैंक का दर्जा भी प्रदान किया गया है। आईपीपीबी की 650 शाखाएं एवं 1,36,078

बैंकिंग सेवा केंद्र हैं। यह बैंक, डाक डिलिवरी एजेंटों के माध्यम से द्वार पर बैंकिंग सेवाएं भी मुहैया कराता है। आईपीपीबी ने अपने प्रचालन के 1 वर्ष से कुछ ही अधिक समय में, 10.03.2020 की स्थिति के अनुसार, 2.26 करोड़ ग्राहक बना लिए हैं और 14,191 करोड़ रु. मूल्य के वित्तीय लेन-देन कार्य किए हैं। इसके अतिरिक्त, आधार संख्या आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के माध्यम से कुल 686 करोड़ रु. मूल्य के 22.04 लाख लेन-देन कार्य भी किए गए हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल आईपीपीबी ने कुल 2096 कार्मिक नियुक्त किए हैं। इनमें सीधी भर्ती के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त कार्मिक भी शामिल हैं। देशभर में स्थित आईपीपीबी शाखाओं की राज्यवार (संघ राज्यक्षेत्र-वार सहित) सूची **अनुबंध - I** में प्रदान की गई है।

(ड.) और (च) आईपीपीबी की ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच को देखते हुए, अनेक वैश्विक तथा घरेलू संस्थानों ने आईपीपीबी के साथ जुड़ने में रुचि दिखाई है, परंतु फिलहाल कोई औपचारिक समझौते नहीं हुए हैं। आईपीपीबी, तृतीय पक्षकारों के उत्पादों के संबंध में भुगतान बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अपने उत्पादों में विस्तार करने के उद्देश्य से, विभिन्न वैश्विक तथा घरेलू संस्थानों के साथ चर्चा कर रहा है।

अनुबंध - I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आईपीपीबी शाखाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	24
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	असम	26
4.	बिहार	38
5.	छत्तीसगढ़	27
6.	दिल्ली	3
7.	गोवा	2
8.	गुजरात * (दादरा एवं नगर हवेली सहित)	32
9.	हरियाणा	20
10.	हिमाचल प्रदेश	12
11.	जम्मू एवं कश्मीर * (लद्दाख सहित)	8
12.	झारखण्ड	22
13.	कर्नाटक	31
14.	केरल * (लक्षद्वीप सहित)	15
15.	मध्य प्रदेश	42
16.	महाराष्ट्र	40
17.	मणिपुर	9
18.	मेघालय	8
19.	मिजोरम	6
20.	नगालैंड	9
21.	ओडिशा	33
22.	पंजाब * (चंडीगढ़ सहित)	23
23.	राजस्थान	33
24.	सिक्किम	1
25.	तमिलनाडु * (पुदुच्चेरी सहित)	37
26.	तेलंगाना	23
27.	त्रिपुरा	5
28.	उत्तर प्रदेश	73
29.	उत्तराखंड	12
30.	पश्चिम बंगाल * (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सहित)	26
	कुल योग	650

*****